

जबलपुर, शुक्रवार 18 सितंबर 2026

login : www.haribhoomi.com

पांडुर्णा | सौंसर | चौरई | बिछुआ | परासिया | जुन्नारदैव | अमरवाड़ा | हरई

35 हजार वर्गफीट पर कब्जा होने तक सुस्त पड़ा था प्रशासन

शिव तीर्थ कॉलोनी में प्लॉट बेचने की तैयारी, मार्केटिंग शुरू, जिम्मेदारों पर कार्यवाही नहीं हुई तो परम्परा बन जाएगा अतिक्रमण

हरिभूमि न्यूज़ » छिन्दवाड़ा

खजरी रोड स्थित दूध डेयरी के आगे निर्माणाधीन शिव तीर्थ कॉलोनी में करीब 35 हजार वर्गफीट शासकीय नाले की जमीन पर अतिक्रमण का मामला राजस्व विभाग की सीमांकन रिपोर्ट के बाद गंभीर हो गया है। राजस्व टीम द्वारा किए गए सीमांकन के बाद तैयार रिपोर्ट में कॉलोनी के सामने करीब 7 हजार वर्गफीट और पीछे करीब 28 हजार वर्गफीट सरकारी नाले की जमीन अतिक्रमण की जट में पाए जाने का उल्लेख है। यानी करीब 35 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की स्थिति सामने आई है। एक तरफ राजस्व जांच में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का उल्लेख है, दूसरी तरफ कॉलोनी में प्लॉटों की बुकिंग के लिए मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। मौके पर प्लॉट बिंदी के लिए लोगों को जानकारी देने और बुकिंग कराने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकारी नाले की जमीन पर अतिक्रमण की स्थिति राजस्व रिपोर्ट में सामने आ चुकी है तो प्लॉटों की बिंदी और बुकिंग किस आधार पर जारी है?

कारवाई नहीं हुई तो बड़ेगा सिलसिला : शिव तीर्थ कॉलोनी का मामला प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब गैद संबंधित अधिकारियों के पाले में है। यदि अतिक्रमण की पुष्टि होने के बावजूद सिर्फ कागजी कार्रवाई होती रही और मौके पर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे गलत संदेश जाएगा। यह स्थिति अपने आप में गंभीर है। प्रशासन को पहले सरकारी जमीन सुरक्षित करनी चाहिए और उसके बाद ही कॉलोनी के वैध हिस्से को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 35 हजार वर्गफीट सरकारी नाले की जमीन पर अतिक्रमण होता रहा, कॉलोनी विकसित होती रही, मार्केटिंग और प्लॉट बुकिंग शुरू हो गई, लेकिन जिम्मेदार विभागों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। यदि अधिकारी और कर्मचारी वास्तव में अनजान थे तो यह उनकी निगरानी व्यवस्था की गंभीर विफलता है।



सिग्नेचर कॉलोनी की कार्रवाई भी सवालों में

शहर में सरकारी नाले की जमीन से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सिग्नेचर कॉलोनी में भी नाले की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया था। कलेक्टर के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की टीम द्वारा सीमांकन किए जाने की बात सामने आई थी और नाले की जमीन पर अतिक्रमण पाया गया था। रिपोर्ट नगर निगम तक पहुंचने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई को लेकर अब भी सवाल उठते रहे हैं।स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह प्रभावी नहीं हुई। यदि ऐसा है तो प्रशासन को दोबारा सीमांकन कराकर स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। सिग्नेचर कॉलोनी के बाद अब शिव तीर्थ कॉलोनी में भी सरकारी नाले की जमीन का मामला सामने आना इस बात की गंभीर जांच की मांग करता है कि आखिर कॉलोनियों में नालों और शासकीय जमीन की निगरानी व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पानी की टंकी पाइपलाइन बिखरी, सरकारी योजना पर सवाल

हरिभूमि न्यूज़ » छिन्दवाड़ा

ग्रामीणों को घर-घर पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी जल योजना की जमीनी हकीकत ग्राम गोनी में व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। गांव में बनाई गई पानी की टंकी और उससे जुड़ी पाइपलाइन की हालत को लेकर निर्माण की गुणवत्ता से लेकर विभागीय निगरानी तक पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर पाइपलाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त और बिखरी दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि व्यवस्था ठीक तरह से शुरू होने से पहले ही पाइपलाइन खराब होने लगी।

सरकारी योजना के तहत लाखों रुपये खर्च कर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना तैयार की गई, लेकिन यदि पाइपलाइन कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो जाती है तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान मानकों का पालन नहीं किया गया। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी। **सरकारी धन खर्च, फिर भी पानी का इंतजार**: ग्राम गोनी की स्थिति ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं के निर्माण और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योजना पर राशि खर्च होने के बाद भी यदि ग्रामीणों को पानी के लिए इंतजार करना पड़े और पाइपलाइन कुछ समय में ही खराब हो जाए तो जिम्मेदार विभाग को इसका जवाब देना



लेकिन पाइपलाइन की बदहाल स्थिति के कारण इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में योजना पर खर्च की गई सरकारी राशि की उपयोगिता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

लागत से लेकर भुगतान तक जांच की मांग

ग्रामीणों ने मांग की है कि योजना की स्वीकृत लागत, निर्माण एजेंसी, कार्यादेश, तकनीकी स्वीकृति, निरीक्षण रिपोर्ट और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाए। साथ ही मौके पर तकनीकी टीम भेजकर टंकी और पूरी पाइपलाइन की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाए।यदि जांच में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल, तकनीकी मानकों की अनदेखी या कार्य में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

होगा।अब ग्रामीणों की नजर विभागीय जांच पर है। सवाल साफ है सरकारी पैसे से बनी जल व्यवस्था की यह हालत क्यों हुई, ग्रामीणों को नियमित पानी कब मिलेगा और खराब पाइपलाइन को ठीक कराने की

जिम्मेदारी किसकी है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला निर्माण में लापरवाही का है या खरखराव की कमी का। फिलहाल ग्राम गोनी में पानी की व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों के बीच नाराजगी बनी हुई है।

न्यूटन पुलिस चौकी ने पकड़े जुआरी , 41 सौ रूपए बरामद

न्यूटन / परासिया : -न्यूटन पुलिस चौकी के नए प्रमारी अविनाश पारधी के नेतृत्व में पुलिस को 4 जुआरी पकड़ने में सफलता हासिल हुई है । जिनके पास से 41 सौ रूपए भी बरामद हुए हैं । पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी , कि चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गाम पंचायत डुंगरिया में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं । जिसके बाद चौकी प्रमारी अविनाश पारधी , ए.एस.आई. रजनीश सोनी , प्र.आर. योनेन्द्र , प्र.आर. सुजान सिंह, आरक्षक सतीश, आरक्षक धनेश्वर , आरक्षक अमित और आरक्षक संदीप मौके पर पहुंचे जहां गाम डुंगरिया की पहाड़ी पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जुआ खेला जा रहा था । पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश के दौरान जुआ खेलते पाए गए चार आरोपियों को पकड़ा गया , जिनके कब्जे से 4,100/- नगद एवं 52 तीश के पत्ते बरामद किये गए । पकड़े गए आरोपीगण:1. नकुल आरसे , उम 22 वर्ष2. ख्यालेस उइके , उम 25 वर्ष3. नितिन दाकरिया , उम 28 वर्ष4. मिथुन कहार , उम 33 वर्षसभी निवासी गाम डुंगरिया, चौकी न्यूटन, थाना परासिया के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

उपयंत्री का अहंकार भरा जवाब-रपटे पर बाढ़ आएगी खड़े होकर देख लेना...

कुआं बादला-नांदिया मार्ग पर रपटा बारिश में बहा, निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज़ » तामिया

कुआं बादला-नांदिया मार्ग पर कुर्सी ढाना के पास नदी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया रपटा मंगलवार शाम हुई बारिश में पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। रपटे के क्षतिग्रस्त होने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उसमें बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि निर्माण में निर्धारित मापदंडों के अनुसार सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। रपटे में लोहे का उपयोग नाममात्र किया गया, वहीं निर्धारित मोटाई के विपरीत कंक्रीट किए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसका



परिणाम बारिश के दौरान पानी के बहाव में देखने को मिला। **जांच से पहले ही हटवा दी कंक्रीट**: रपटा बहने के बाद मामले में एक और गंभीर सवाल उठ रहा है। आरोप है कि ठेकेदार की कथित

गलती को छिपाने के लिए विभाग के उपयंत्री द्वारा अपने विभाग के स्थायी मजदूरों को मौके पर भेजकर रपटे की क्षतिग्रस्त कंक्रीट को तुड़वाकर एक तरफ करवा दिया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि किसी

तकनीकी जांच अथवा गुणवत्ता परीक्षण के पहले ही कंक्रीट हटाए जाने से निर्माण में उपयोग की गई सामग्री और वास्तविक मोटाई की जांच प्रभावित हो सकती है। लोगों का आरोप है कि यदि रपटे की कंक्रीट और निर्माण सामग्री की जांच होती तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती थी।रपटे के बहने और कंक्रीट हटाए जाने के बाद अब इस मार्ग पर बने अन्य पुल-पुलियों के निर्माण कार्य भी जांच के घेरे में आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पूरे मार्ग पर बने रपटों और पुलियों की तकनीकी जांच कराई जाए तो निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

नपा कार्यालय के बाहर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन

सौंसर। नगर में गणेशोत्सव और महालक्ष्मी जैसे बड़े और पवित्र त्योहारों के बीच नगर की बुनियादी व्यवस्थाएं जैसे पेयजल साफ सफाई कचरा गाड़ी आदि चरमरा गई हैं। गुरुवार को पानी की किल्लत, अनियमित कचरा संग्रहण और खराब स्ट्रीट लाइट जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर नगर युवा कांग्रेस सौंसर के शिटमंडल ने नपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौसम पालेवाल को एक ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञात हो कि पाइपलाइन खराब होने के चलते विगत तीन दिनों से सौसर नगर के वार्ड क्रमांक 5 6 7 के निवासियों के नल से पानी नहीं आ रहा था, जिसके चलते वार्ड वासियों को परेशान होना पड़ रहा था। नपा प्रशासन को ज्ञापन सौंपने आए कांग्रेस नेता विलास बुले, नगर युवा अध्यक्ष प्रफुल्ल कडू ने बताया कि नगर के लगभग आधे वार्डों में पिछले 3 से 4 दिनों से नल नथ आने से जल आपूर्ति पूरी तरह ठप है। त्योहार के दिनों में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ऐसे में जलापूर्ति बंद रहने से नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है।

कई वार्डों में प्रतिदिन आने वाली कचरा गाड़ी 4 से 5 दिन के अंतराल पर पहुंच रही है, जिससे जगह-जगह गंदगी और कचरे के ढेर बढ़ रहे हैं। नगर की नालियों की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है, वहीं खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों के कारण नगर के रास्तों पर अंधेरा छाया रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर अतिशोध स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की मांग की गई है। समस्या का समाधान नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान कांग्रेस नेता डॉ शिवकुमार सालोटरकर,अमोल आनोटरकर अनुभव सूषे, नितिन बोडखे,आदि उपस्थित थे।

35 हजार वर्गफीट पर अतिक्रमण, जिम्मेदारों को खबर नहीं थी?

यह मामला सिर्फ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। असली सवाल उस व्यवस्था पर है, जिसकी निगरानी में यह पूरा विकास हुआ। यदि राजस्व विभाग की टीम सीमांकन के बाद करीब 35 हजार वर्गफीट शासकीय नाले की जमीन अतिक्रमण में पाती है तो सवाल उठना लाजिमी है कि जब जमीन पर निर्माण और कॉलोनी का विकास हो रहा था, तब जिम्मेदार विभागों के अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे थे?क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी या जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई? यदि कार्रवाई नहीं की गई तो इसकी वजह क्या थी? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को देना चाहिए।

पहले एफआईआर , फिर जिम्मेदारों की जांच

यदि राजस्व रिपोर्ट में सरकारी नाले की जमीन पर करीब 35 हजार वर्गफीट अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो सिर्फ अतिक्रमिता हिस्से को हटाना ही पर्याप्त नहीं होगा। अतिक्रमण कैसे हुआ, किसकी अनुमति से हुआ, किस स्तर पर निगरानी नहीं की गई और कार्रवाई में देरी क्यों हुई—इन सभी बिंदुओं की जांच जरूरी है।शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार आपराधिक कार्रवाई और एफआईआर की मांग भी उठ रही है। साथ ही उन अधिकारी-कर्मचारियों की विभागीय भूमिका की जांच होना चाहिए, जिनके कार्यक्षेत्र में यह जमीन और निर्माण आता है।क्योंकि यदि आज 35 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है और जिम्मेदारों की भूमिका की जांच नहीं होती, तो कल किसी दूसरी कॉलोनी में इससे बड़ा मामला सामने आ सकता है।

दुकानों में नजर नहीं आ रही रेट लिस्ट

बार-बार खबरों के बाद भी कार्रवाई नहीं, आबकारी अमले की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

हरिभूमि न्यूज़ » छिन्दवाड़ा

शहर की कम्पोजिट शराब दुकानों पर आबकारी नियमों की अनदेखी का मामला एक बार फिर सामने आया है। विभागीय निर्देशों के बावजूद शहर की अधिकांश शराब दुकानों पर शराब की अधिकृत मूल्य सूची यानी रेट लिस्ट नजर नहीं आ रही है। रेट लिस्ट के अभाव में ग्राहक को यह जानकारी नहीं मिल पाती कि वह जिस ब्रांड की शराब खरीद रहा है, उसकी निर्धारित कीमत कितनी है। ऐसे में दुकानदारों द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

बताया जा रहा है कि आबकारी नियमों के तहत शराब दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है, ताकि ग्राहक को शराब की वास्तविक कीमत की जानकारी मिल सके और निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की स्थिति में वह इसकी शिकायत कर सके। इसके बावजूद शहर की कई दुकानों पर रेट लिस्ट दिखाई नहीं दे रही है।

खबरें बार-बार प्रकाशित,

कार्रवाई अब तक क्यों नहीं?

रेट लिस्ट गायब होने को लेकर पहले भी खबरें प्रकाशित होती रही हैं। इसके बावजूद यदि स्थिति जस की तस बनी हुई है तो यह जिला आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी है कि आखिर जिला आबकारी अधिकारी कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या विभागीय टीमें नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण नहीं कर रही हैं? यदि निरीक्षण हो रहा है तो नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई देती?सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं शराब ठेकेदारों के प्रभाव के कारण आबकारी अमला कार्रवाई से पीछे तो नहीं हट रहा? क्या विभागीय अधिकारियों के हाथ किसी दबाव के कारण बंधे हुए हैं? हालांकि इस संबंध में किसी प्रकार का ठोस तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार रेट लिस्ट नहीं लगाए जाने और खबरें प्रकाशित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है।



अधिकारी

बोले- जांच कराएंगे

इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी बी.आर. वैद्य ने कहा कि सभी कम्पोजिट शराब दुकानों में अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। यदि इसके बावजूद किसी दुकान पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो टीमों से जांच कराई जाएगी और सभी दुकानों पर जल्द से जल्द रेट लिस्ट लगवाना सुनिश्चित किया जाएगा।।सब देखना यह है कि अधिकारी के इस आश्वासन के बाद वास्तव में शहर की सभी शराब दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित होती है या फिर मामला सिर्फ निर्देश और आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है। शराब खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हित में जरूरी है कि रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे और निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर विभाग तत्काल कार्रवाई करे। आखिरकार नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की ही है, और यदि नियमों की अनदेखी लगातार होती रही है तो आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा कौन करेगा?

बीना की घटना के बाद भी नहीं चेता

अमला

हाल ही में मध्यप्रदेश के बीना में शराब दुकान से जुड़ी घटना के बाद शराब दुकानों की व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठे थे। इसके बावजूद छिंदवाड़ा में आबकारी विभाग का स्थानीय अमला शराब दुकानों पर रेट लिस्ट की अनिवार्यता को लेकर सख्ती बरतता नजर नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि जब विभागीय अधिकारियों को नियमों की जानकारी है और दुकानदारों को रेट लिस्ट लगाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं, तो फिर मौके पर इसका पालन क्यों नहीं कराया जा रहा?

शुरुआत में लगी,

फिर गायब हो गई

स्थानीय लोगों के अनुसार, शराब दुकानों पर शुरुआत में रेट लिस्ट लगाई गई थी, लेकिन कुछ समय बाद कई दुकानों से यह सूची हटा दी गई। अब स्थिति यह है कि ग्राहक दुकान पर पहुंचने के बाद शराब की बोतल की कीमत को लेकर पूरी तरह दुकानदार पर निर्भर हो जाता है। निर्धारित कीमत की जानकारी नहीं होने के कारण ग्राहक के पास तत्काल तौर पर यह जांचने का कोई आसान माध्यम नहीं रहता कि उससे ली जा रही राशि सही है या नहीं।यह स्थिति उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय है जो नियमित रूप से शराब खरीदते हैं।

कार्यालय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित (बी पैवस) कर्णुर्षा		
पंजीजन क्रमांक 847 दिनांक : 31/10/1966		
क/कयु।आमसमा/2026/	वार्षिक आमसभा सूचना-पाठ	दिनांक- 15 सितम्बर 2026
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित (बी पैवस) कर्णुर्षा पं. क्र.847 दिनांक 31/10/1966 के समस्त अंशधारी कृषक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था का साधारण वार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 28.09.2026 दिन शनिवार को संस्था कार्यालय भवन कर्णुर्षा में दिन के 12.30 बजे आयोजित की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति प्राथनीय है।		
विषय सूची : -1. आगामी वर्ष 2026-27 के लिये किया गया पौ एवं कार्यकाल पर विचार।2- संवाक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन यदि करार्या जाना अपेक्षित है, पर विचार।3- वर्ष 2025-26 के ऑडिट प्रतिवेदन (संपरीक्षा प्रतिवेदन) का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान करना।4- वर्ष 2025-26 के शुद्ध लाभ के व्ययन बाबत पर विचार।5- आगामी सहकारी वर्ष 2026-27 के लिये बजट प्रस्तुत करने बाबत पर विचार।6- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य संचालन के कारण हुए घटे के कारणों का परीक्षण करने बाबत विचार।7- वर्ष 2026-27 लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये संपरीक्षक की नियुक्ति करने बाबत विचार।7- वर्ष 2026-27 लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये संपरीक्षक की नियुक्ति करने बाबद।8. अधीक्षियम / उपबिधि के प्रावधान अनुसार अतिरिक्त व्यय के ज्ञान पर विचार।9- अन्य विषय प्रशासन एवं आमसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।		
नोट : - कोरम के अभाव में साधारण वार्षिक आमसभा की बैठक आधा घंटे के लिये स्थगित की जावेगी आधा घंटे पश्चात बैठक पुनः उसी स्थान पर परमत्र की जावेगी जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।		
श्रीमती शीता पटेल, प्रशासक		रमेश वर्मा, प्रबंधक
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित कर्णुर्षा हठ.-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा		

कार्यालय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित (बी पैवस) समयसत्र	पंजीजन क्रमांक 844, दिनांक : 31.10.1966	दिनांक 05/09/2026
कर्मांक / कयु।आमसमा/ 2026 / समयसत्र	आमसभा सूचना पत्र	बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित (बी पैवस) समयसत्र पं. क्र0 844 दिनांक 31/10/1966 के समस्त अंशधारी सदस्यों को सूचित किया जाता है, कि संस्था का साधारण वार्षिक आमसभा दिनांक 26/09/2026 दिन शनिवार को संस्था कार्यालय समयसत्र में दिन के 01:30 बजे आयोजित की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति प्राथनीय है। विषय सूची:- 1. आगामी वर्ष 2026-27 के लिये किया गयापौ एवं कार्यकाल पर विचार।2. संवाक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन यदि करार्या जाना अपेक्षित है, पर विचार।3. प्राप्त संपरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2025-26 पर विचार बाबद।4. वर्ष 2026-27 के शुद्ध लाभ के व्ययन बाबद विचार।5. आगामी सहकारी वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करने बाबद विचार।6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य संचालन के कारण हुए घटे के कारणों का परीक्षण करने बाबद विचार।7. वर्ष 2026-27 लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये संपरीक्षक की नियुक्ति करने बाबद।8. अधीक्षियम / उपबिधि के प्रावधान अनुसार अतिरिक्त व्ययन के प्लान पर विचार।9. अन्य विषय अध्यक्ष / प्रशासन महोदय की अनुमति से। टीप:- 1. कोरम के अभाव में साधारण वार्षिक आमसभा की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित की जावेगी, आधा घंटे पश्चात बैठक पुन: उसी स्थान पर परमत्र की जावेगी, जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, तथा स्थगित आमसभा बैठक उपर्युक्त एजेंडे के अतिरिक्त अन्य विषयों पर निर्णय नहीं लिये जा सकेगी।



10 साल से अटैचमेंट पर शिक्षक, एक ओर शिक्षकों की कमी तो दूसरी ओर विभाग में बैठे कर्मचारी

ई-अटेंडेंस लगाई और स्कूल से गायब!

हरिभूमि न्यूज ॥ छिन्दवाड़ा

स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शासन ने ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू की है, लेकिन जिले में इस की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत है कि एक शिक्षक स्कूल में ई-अटेंडेंस लगाकर

इसके बाद स्कूल से गायब हो जाता है और छिंदवाड़ा में आकर बैठ जाता है। बताया जा रहा है कि संबंधित शिक्षक करीब 10 वर्षों से अटैचमेंट पर है और इतने लंबे समय से अपने मूल पदस्थापना वाले स्कूल में नियमित अध्यापन नहीं कर रहा। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि एक तरफ ग्रामीण और दूरस्थ स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक वर्षों से मूल स्कूल से दूर रहकर अटैचमेंट का लाभ ले रहे हैं।

हाजिरी स्कूल में, मौजूदगी कहाँ?

शिकायत के अनुसार शिक्षक मैदानी क्षेत्र के स्कूल में ई-अटेंडेंस दर्ज करने के बाद छिंदवाड़ा आने-जाने में लगा रहता है। यदि यह सही पाया जाता है तो सिर्फ ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में आ जाता है। ई-अटेंडेंस का मकसद केवल मोबाइल पर उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, बल्कि शिक्षक की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इसलिए विभाग को यह जांचना चाहिए कि संबंधित शिक्षक स्कूल में हाजिरी लगाने के बाद वास्तव में कक्षा में मौजूद रहता है या नहीं।

10 साल में कितनी कक्षाएं लीं?

यदि शिकायत सही है और संबंधित शिक्षक ने करीब दस वर्षों से अपने मूल स्कूल में जाकर नियमित रूप से अध्यापन नहीं किया है तो बड़ा सवाल है कि वह किस काम का वेतन ले रहा है? शिक्षक का मूल दायित्व विद्यार्थियों को पढ़ाना है। ऐसे में वर्षों तक कक्षा से दूर रहने की स्थिति में उसकी सेवा और वेतन की समीक्षा अब तक क्यों नहीं की गई? दस साल तक अटैचमेंट बने रहना अपने आप में जांच का विषय है। विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित शिक्षक को इतने लंबे समय तक अटैचमेंट पर रखने का आदेश किस स्तर से जारी हुआ और इसकी समय-समय पर समीक्षा क्यों नहीं हुई।

मूल स्कूल में, प्रशिक्षण भी कराएं

शिक्षा विभाग को जिले में लंबे समय से अटैचमेंट पर कार्यरत शिक्षकों की सूची तैयार कर उनकी वास्तविक स्थिति की जांच करनी चाहिए। जो शिक्षक वर्षों से अपने मूल पदस्थापना स्थल पर अध्यापन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मूल स्कूल भेजना चाहिए यदि कोई शिक्षक लंबे समय से कक्षा से बाहर है तो उसकी विषयगत और अध्यापन क्षमता की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार पुनः प्रशिक्षण भी करया जाना चाहिए।

विभाग की मेहरबानी या प्रभाव का खेल?

सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर है। यदि किसी शिक्षक का अटैचमेंट करीब दस साल से चला आ रहा है तो अधिकारियों ने इसकी समीक्षा क्यों नहीं की? क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आड़ में यह व्यवस्था चलती रही? एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी और दूसरी तरफ वर्षों से अटैचमेंट पर बैठे शिक्षक—यह शिक्षा व्यवस्था की बड़ी चिड़बुका है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग शिकायत की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाता है या फिर मामला कागजों में ही सिमटकर रह जाता है।

डोलोमाइट का अवैध परिवहन, अमला ने धरा ट्रैक्टर

हरिभूमि न्यूज ॥ पाहुर्णा

कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए शिक्षण विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज 17 सितंबर 2026 को खनिज विभाग के दल द्वारा तहसील सौसर अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान रमण्ड-बोरगांव मार्ग पर खनिज डोलोमाइट का अवैध रूप से परिवहन करते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एएमएच 40 बीई 7589 मय ट्रॉली पाए जाने पर खनिज विभाग के दल द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई। वाहन को खनिज नियमों के प्रावधानों के



अंतर्गत शासकीय रूप से जप्त कर खनिज डोलोमाइट सहित पुलिस थाना लोधीखेड़ा परिसर में शासकीय अभिरक्षा में खड़ा कराया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक खनि अधिकारी श्री महेश नगपुरे एवं खनिज विभाग का संयुक्त अमला उपस्थित रहा।

खनिज के अवैध परिवहन के संबंध में नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण में जुर्रमाना राशि अधिव्यवित्त किए जाने हेतु निर्णय के लिए माननीय कलेक्टर न्यायालय, पाहुर्णा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

सोनपुरी में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संदीप गजगुप्ते एवं अमन गोयाम उपस्थित रहे। वहीं विश्वकर्मा आदर्श लोहार समाज संगठन, उकवा के अध्यक्ष सालिकराम बावने, उपाध्यक्ष आशाराम सोनवाने एवं समाज संगठन मंत्री पितरलाल मंसवार सहित

विश्वकर्मा आदर्श लोहार समाज संगठन, उकवा के तत्वावधान में हुआ आयोजन, हवन-पूजन के बाद भंडारा प्रसादी का वितरण

हरिभूमि न्यूज उकवा।

ग्राम सोनपुरी में विश्वकर्मा आदर्श लोहार समाज संगठन, उकवा के तत्वावधान में भगवान विश्वकर्मा जयंती श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में भगवान विश्वकर्मा जी की विधि-

विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि, सफलता एवं समाज की उन्नति की कामना की गई। पूजन के पश्चात उपस्थित समाजजनों एवं ग्रामीणों के लिए भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया। भगवान विश्वकर्मा जी सुजन, श्रम और कौशल के प्रतीक हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होती हैं और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्यक्रम में सोनपुरी, दलदला, उकवा, नव्ही, लातरी, बड़ी घोंदी, चिखलाझोड़ी एवं उमरिया सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर निशति विश्वकर्मा, धूपसिंग सोनवाने, नंदाबाई बघेल, राजेन्द्र मंसवार, उर्मिला बाई पन्डाम, दीपक मंसवार, नरेश पथिये, राजू पन्डाम, रम्भुलाल सहजवार, दिनेश लांजेवार, पुनाराम बावने, संतोष धुवे, परस्राम बावने, नंदुलाल, प्रदीप धनकटे, प्रमोद मरकाम, शिवम बर्वे सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। आयोजन के माध्यम से समाज में एकता, सहयोग, भाईचारा एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने और शिक्षा व संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया।

प्रभावित बच्चों और उनके परिजनों के लिए भोजन-नाश्ते के साथ राशन की व्यवस्था बिठली, सोनगुड़ा और बिरसा के उपस्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की सेवा

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। वनांचल के दूरस्थ और बैगा बहुल गांवों में लंबे समय से सामाजिक सेवा के माध्यम से ग्रामीणों से जुड़ने वाले रामेश्वर कटरे इन दिनों स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार करा रहे प्रभावित बच्चों और उनके परिजनों की मदद में जुटे हैं। बुधवार 16 सितंबर को उन्होंने दक्षिण बैहर के बिरसा, सोनगुड़ा और बिठली के उपस्वास्थ्य केंद्रों के साथ बैहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से संवाद किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की जानकारी लेने के साथ जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन, नाश्ता और राशन सामग्री की व्यवस्था की गई।

बिठली में क्षमता से अधिक बच्चों पहुंचे, भोजन व्यवस्था पर पड़ा असर : बिठली स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचे प्रभावित बच्चों की संख्या उपलब्ध बेड की क्षमता से अधिक हो गई। बच्चों के साथ उनके माता-पिता और भाई-बहन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। इससे मरीजों के साथ आए परिवारों के भोजन की व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। चिकित्सकों ने फोन पर इसकी

जानकारी रामेश्वर कटरे को दी। इसके बाद वे साथियों के साथ बिठली पहुंचे और स्थिति को समझते हुए भोजन व्यवस्था में सहयोग किया। इसके बाद सोनगुड़ा, बिरसा और बिठली में मरीजों और उनके परिजनों के लिए राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। सुबह-शाम नाश्ते और भोजन की व्यवस्था भी की गई।

मरीजों से संवाद और सहायता से सामने आया भरोसे का बदलाव - रामेश्वर कटरे

बिरसा, सोनगुड़ा और बिठली के स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर श्री कटरे ने मरीजों और उनके परिजनों से उनकी समस्याओं तथा उपचार को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि बाच्यीत के दौरान कई लोगों ने कहा कि अब



स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर वे पहले अस्पताल पहुंचें और चिकित्सकों से उपचार कराएं। श्री कटरे का कहना है कि "पहले लोगों के मन में अस्पताल जाने को लेकर डर और संकोच था। अब वे खुद बच्चों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं। 15 वर्षों से बैगा गांवों में सेवा का सिलसिला, सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर कटरे पिछले करीब 15 वर्षों से दक्षिण बैहर के दूरस्थ वनांचल और बैगा बहुल गांवों में

सामाजिक सेवा से जुड़े हैं। कुकड़ा, कोरका, मातला, धर्मशाला, कुंडेकशा और कोहनीमोर सहित अन्य गांवों में पहुंचकर उन्होंने बच्चों और महिलाओं की जरूरतों के अनुसार कपड़े, जूते-चप्पल, मच्छरदानी और दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया है।

मंत्री कुंवर विजय शाह ने भी की सेवा कार्यों बैगा ग्रामों में किए जा रहे सामाजिक सेवा कार्यों की मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री कुंवर विजय शाह ने भी मुक्त कंठ से सराहना की थी। दूरस्थ आदिवासी अंचल में लगातार पहुंचकर ग्रामीणों और जरूरतमंद परिवारों के बीच किए जा रहे सेवा कार्यों को उन्होंने सराहा। कटरे का कहना है कि ऐसे प्रयास तभी प्रभावी हो सकते हैं, जब समाज के अन्य सक्षम लोग भी आगे आकर सहयोग करें।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहुंचा बैगा बच्चों की मौतों का मामला-विक्रम देशमुख

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। जिला पंचायत बालाघाट के पूर्व सदस्य, इंजीनियर विक्रम देशमुख द्वारा विकासखंड बिरसा में आदिवासी बैगा बच्चों की रहस्यमयी मौतों की उच्चा स्तरीय जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली में दिनांक 05/9/2026 को शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए विक्रम देशमुख द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में भी सितंबर माह में आदिवासी बच्चों की मौतों को लेकर याचिका दर्ज कराई गई है। जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना का संज्ञा लेकर डायरी क्रमांक 20725 दर्ज किया है।

श्री देशमुख द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के विकासखंड बिरसा में जून के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर माह तक हुई आदिवासी बैगा बच्चों

रसोईया संघ ने चूल्हा फूंकना किया बंद, नौनिहालों को नहीं मिल रहा भोजन, 4 महीने से मानदेय नहीं



पांडुर्णा। शासन की संवेदनहीनता के चलते जिले के सरकारी स्कूलों में नौनिहालों का निवाला छिन गया है। प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ के आह्वान पर मध्यप्रदेश मंत्रालय शांति चूल्हा रसोइया संघ बीते 16 सितंबर से बैगियाड़ी हड़ताल पर चला गया है। 4 महीने से मानदेय और भोजन सामग्री की राशि न मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने चूल्हा फूंकना बंद कर दिया है, जिससे पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हड़ताल के पहले दिन स्कूलों में पूरी तरह सन्नाटा पसर रहा और बच्चों को भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। वहीं आज, 17 सितंबर को कुछ स्कूलों ने जैसे-तैसे अपने स्तर पर भोजन की व्यवस्था तो की, लेकिन यह दर्रा कब तक चलेगा? सवाल यह उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन इन गरीब महिलाओं से बंधुआ मजदूरी कराना चाहते हैं? उधार के भरोसे कब तक पकेगा भोजन : संघ का स्पष्ट कहना है कि शालाओं और आंगनवाड़ियों का पिछले चार महीनों का भुगतान अटका पड़ा है। दुकानदारों ने अब राशन उधार देना बंद कर दिया है। रसोइया महिला कल्पना कलंबे का दर्द "महज 4 हजार रुपये प्रति माह के मामूली मानदेय पर हम दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन वह भी समय पर नहीं मिलता। इस महंगाई में घर चलाएं या अपनी जेब से बच्चों के भोजन का राशन जुटाएं?" इस कथन से सामने आ गया। रसोईया संघ की प्रमुख मांगें :- रसोईया संघ के अनुसार पिछले 4 माह का बकाया राशन और मानदेय तुरंत जारी किया जाए, पिछले तीन वर्षों का 15 दिन का रुका हुआ भुगतान तथा जून 2024, 2025 और 2026 की बची हुई राशि तुरंत दी जाए, हर महीने मानदेय और मध्यान्ह भोजन की राशि के भुगतान के लिए एक तय तारीख घोषित की जाए, गेहूं और चावल की पर्याप्त एवं उचित मात्रा सुनिश्चित की जाए। रसोईया संघ ने कहा कि, शासन-प्रशासन की नकारा कार्यशैली के कारण आज गरीब और असहाय रसोइया महिलाएं सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। अगर समय रहते प्रशासन की नौद नहीं खुली और बकाया राशि का तत्काल भुगतान नहीं किया गया, तो यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

विश्वकर्मा जयंती पर चौरई में आस्था का सैलाब

हवन-पूजन के बाद निकली शोभायात्रा, समाजजनों ने लिया भोज का प्रसाद

हरिभूमि न्यूज ॥ चौरई

भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को चौरई में सकल विश्वकर्मा समाज समिति के तत्वावधान में भव्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधि-विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापना से हुई। इसके पश्चात श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हवन-पूजन एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें



विश्वकर्मा समाज के बड़ी संख्या में समाजजन उत्साह और श्रद्धाभाव के साथ शामिल हुए। भगवान विश्वकर्मा जी के जयकारों से नगर

शोभायात्रा के पश्चात समाजजनों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं जयंती समारोह की शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया।

रात में कलाकारों ने भक्तिमय प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया और देर रात तक भगवान विश्वकर्मा जी की भक्ति में पूरा माहौल सराबोर रहा। कार्यक्रम में समाज के लोगों की बड़ी सहभागिता ने आयोजन को भव्य रूप दिया। पूजन से लेकर शोभायात्रा, सामूहिक भोज और भजन संध्या तक पूरे दिन चौरई में भगवान विश्वकर्मा जयंती की धूम रही।

दिलीप भट्टे शासकीय महाविद्यालय में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम संपन्न, 500 दीपों से रोशन हुआ परिसर



हरिभूमि न्यूज किरनापुर।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग (सतपुड़ा भवन, भोपाल) के निर्देशानुसार स्व. दिलीप भट्टे शासकीय महाविद्यालय, किरनापुर में प्राचार्य डॉ सुनिता जैन, नोडल अधिकारी डॉ. पल्लवी रिनहिटे के मार्गदर्शन में रसेवा संकल्प अभियान-2026 का आयोजन किया जा रहा है।

अभियान के प्रथम चरण में 17 सितम्बर 2026 को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन हुआ, जिसमें परिसर में विद्यार्थियों की सहभागिता से 500

दीपों का सामूहिक प्रचलन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती गायत्री केकती द्वारा प्रस्तुत मधुर स्वागत गीत से हुआ। प्राचार्य डॉ. सुनीता जैन ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में सेवा भाव के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही पूर्व छात्रों एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने व्याख्यान के माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम की संयोजक सुशी साक्षी बंसोड़ रही।

इस संपूर्ण अभियान को सफल बनाने में महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्र-छात्राओं का विशेष सहयोग एवं योगदान रहा।

रेल हादसे में गंवाए थे दोनों पैर, बीमारी से हुई मौत, कोष्टी समाज ने कराया अंतिम संस्कार

वारासिवनी। वारासिवनी नगर के गोलीबारी चौक स्थित पुरानी गुड़ मंडी में वर्षों से रह रहे निधन परिवार के युवक संदीप धकाते की बीमारी के चलते मौत हो गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अंतिम संस्कार में परेशानी की जानकारी मिलने पर कोष्टी समाज ने आगे बढ़कर परिवार की मदद की और अंतिम संस्कार कराया। संदीप अपनी मां मुन्नी बाई के साथ गुड़ मंडी में रहता था। गत वर्ष गोंदिया से वारासिवनी लौटते समय रेल हादसे में उसके दोनों पैर कट गए थे। उपचार के बाद वह ठीक हो गया था। लेकिन 14 सितंबर को अचानक तबीयत बिगडने पर उसे शासकीय अस्पताल वारासिवनी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां 15 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

खबर संक्षेप

नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती के निर्देश, दवा दुकानों से लेकर अवैध शराब तक होगी सतत निगरानी

हरिभूमि न्यूज़ सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनकोर्ड समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा की उपस्थिति रही। बैठक में जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध शराब के निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण तथा नशा मुक्ति अभियान को गति देने के लिए विभागावार कार्रवाई एवं आगामी कार्योजना की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने निर्देश दिए कि जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर सतत निगरानी रखें और आपसी समन्वय के साथ निगमनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने नशीले पदार्थों की उपलब्धता, अवैध बिक्री, परिवहन एवं उपयोग की रोकथाम के लिए विभागों को सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से पालन करने तथा कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

लंबित प्रकरणों में साक्ष्य संकलन एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश

हरिभूमि न्यूज़ सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने सख्तीनखेज, गंभीर एवं आपराधिक प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी, अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री सहित पुलिस, वन एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरणों में अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा कर प्रकरणों में आवश्यक साक्ष्य मजबूत करने, पीड़ितों एवं गवाहों को आवश्यक सहाय्य उपलब्ध कराने तथा न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने पर विशेष ध्यान देना रहा। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की जानकारी ली।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने दिए सख्त निर्देश

हरिभूमि न्यूज़ सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी, अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआइ), एमपीआरडीसी, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में एकिकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस आई-रैप तथा थानों में दर्ज प्रकरणों के आधार पर गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों और उनके कारणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्रीमती मीना ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन से जुड़े कार्यों को संबंधित विभाग आपसी समन्वय से प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें, इसके निर्देश दिए।कलेक्टर श्रीमती मीना ने यातायात पुलिस को वाहन चालकों द्वारा हेल्मेट, सीट बेल्ट सहित अन्य सड़क सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जागरूकता एवं जांच अभियान चलााने के निर्देश दिए।

सेवा संकल्प अभियान से विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना होगी मजबूत-डॉ चौरासे

हरिभूमि न्यूज़ ►►सिवनी।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय विधि महाविद्यालय में जागरूकता एवं प्रेरणात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें दीप उत्सव, वृक्षारोपण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, कार्यक्रम में जिला टेबल टेनिस एसोशियन के सचिव संदीप मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राकेश कुमार चौरासे ने कहा कि सेवा केवल किसी व्यक्ति की सहायता करना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्व का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करना है। विद्यार्थियों में सेवा, संवेदना, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना

ग्रामीणों की जान से खिलवाड़: धनौरा विकासखंड में फैला झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों का मकड़जाल

स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का फायदा उठाकर सुदूर ग्रामीण अंचलों में खुले अवैध क्लीनिक

बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के घड़ल्ले से दी जा रही है हाईडोज दवाइयां और स्टेरॉयड, मासूमों की जिंदगी दांव पर

धनौरा। सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य धनौरा विकासखंड इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों, विशेषकर खुद को 'बंगाली डॉक्टर' बताने वाले कथित चिकित्सकों के मकड़जाल में फंसा हुआ है। क्षेत्र के सुदूर गांवों से लेकर विकासखंड मुख्यालय तक, बिना किसी वैध डिग्री और स्वास्थ्य विभाग के रजिस्ट्रेशन के दर्जनों अवैध क्लीनिक संचालित हो रहे हैं। इलाज के नाम पर ये झोलाछाप सीधे तौर पर मासूम और सीधे-साधे ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठा है।

गांव-गांव फैली हैं अवैध क्लीनिक की जड़ें

धनौरा मुख्यालय सहित इसके अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव में इन झोलाछाप डॉक्टरों ने अपने पैर पसार लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वा अन्य राज्यों से आकर ग्रामीण क्षेत्रों में बस गए ये कथित डॉक्टर सामान्य सर्दी-खांसी से लेकर गंभीर बीमारियों तक का इलाज करने का दावा करते हैं। इन दुकानों नुमा क्लीनिकों में मरीजों को बिना किसी जांच के सीधे ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जाती हैं और भारी मात्रा में स्टेरॉयड व प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं।

मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़, पहले भी आ चुके हैं मामले

हाल ही में धनौरा क्षेत्र से कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां झोलाछाप डॉक्टरों के गलत इलाज के कारण मासूम बच्चों की तबीयत बेहद नाजुक हो गई। स्थानीय लोगों की



शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को कार्रवाई के निर्देश भी दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई न होने के कारण इन फर्जी डॉक्टरों के हौसले बुलंद हैं। कभी-कभार तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एकाध क्लीनिक सील करने की खानापूर्ति की जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये दोबारा नए नाम से अपनी अवैध दुकानें खोल लेते हैं।

प्रशासनिक संरक्षण या विभागीय लापरवाही

ग्रामीणों का आरोप है कि इन अवैध क्लीनिकों की जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य अमले को

पूरी तरह होती है। इसके बावजूद महीनों तक इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती। झोलाछाप डॉक्टरों का यह नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि वे खुलेआम मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज करते हैं और बायोमेटिकल वेस्ट (इस्तेमाल की गई सुई, सिरिज, दवाइयां) को खुले में फेंककर संक्रमण की बीमारी को न्योता देते हैं।

सस्ते और त्वरित इलाज के झांसे में फंस रहे ग्रामीण

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और जागरूकता के अभाव के कारण ग्रामीण इन झोलाछाप डॉक्टरों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। त्वरित आराम देने के चक्कर में ये डॉक्टर मरीजों को भारी डोज दे देते हैं, जिससे एक बार तो आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में मरीजों के लिवर और किडनी खराब होने जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

क्षेत्र में अवैध रूप से क्लीनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टरों की सूची तैयार की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को बिना वैध डिग्री के प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जल्द ही पुलिस और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक बड़ा संयुक्त छापामार अभियान चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी

19 सितंबर को जैतपुर कलां में होगा विशाल इनामी दंगल

146 वर्षों से चली आ रही परंपरा, पंजाब-हरियाणा-दिल्ली सहित कई राज्यों के पहलवान होंगे शामिल

सिवनी के समीपस्थ ग्राम जैतपुर कलां में 19 सितंबर, शनिवार को दोपहर 2 बजे से विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया जाएगा।

हरिभूमि न्यूज़ ►►सिवनी।

आयोजन समिति द्वारा दंगल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परंपरागत रूप से राधाष्टमी की पवित्र तिथि पर आयोजित होने वाला यह दंगल इस वर्ष अपनी 146 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा।



आयोजन समिति के सदस्य बसंत बघेल ने बताया कि दंगल का उद्देश्य भारतीय मल्लविद्या की पुरातन परंपरा को जीवित रखना और नई पीढ़ी को कुश्ती जैसी पारंपरिक खेल विधा से जोड़ना है।

लगातार 146 वर्षों से आयोजित हो रहे इस दंगल ने क्षेत्र में अपनी अलग

पहचान बनाई है। इस वर्ष आयोजित होने वाले दंगल में सिवनी जिले के अलावा अन्य जिलों और राज्यों से भी पहलवानों के पहुंचने की संभावना है।

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों के पहलवान अपने दांव-पेंच का प्रदर्शन करेंगे। कुश्ती

महिलाओं ने श्रद्धा-भाव से किया संतान सातमी व्रत-पूजन

संतान की सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना को लेकर महिलाओं ने विधि-विधान से की पूजा-अर्चना

हरिभूमि न्यूज़ ►►सिवनी।

नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संतान सातमी का व्रत एवं पूजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने एकत्रित होकर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया तथा अपनी संतान की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। संतान सातमी के अवसर पर महिलाओं ने पूजन स्थल पर विभिन्न पूजन सामग्री सजाकर भगवान का स्मरण किया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना करते हुए दीप प्रज्वलित किए और धार्मिक विधियों के साथ व्रत की पूजा संपन्न की। इस दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे के साथ पर्व की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को साझा किया। पूजा स्थल पर महिलाओं की सहभागिता से भक्तिमय वातावरण बना रहा। व्रत रखने वाली महिलाओं ने संतान की



खूशहाली और परिवार में सुख-शांति को कामना करते हुए पूजा-अर्चना की। संतान सातमी का पर्व मातृत्व की आस्था और संतान के प्रति ममता से जुड़ा पर्व माना जाता है। महिलाओं

द्वारा इस दिन व्रत रखकर संतान के मंगल एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। पर्व को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

रोजगार मेले में 463 का प्रारंभिक चयन

सिवनी, कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशन में जिला प्रशासन, जिला रोजगार कार्यालय सिवनी, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सिवनी, शासकीय आईटीआई छपारा एवं शासकीय महाविद्यालय छपारा के संयुक्त तत्वाधान में 16 सितंबर 2026 को शासकीय महाविद्यालय छपारा में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 12 विभिन्न कंपनियों ने सहभागिता की। मेले में जिले के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 528 आवेदकों ने अपना पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार के लिए 463 आवेदकों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। वहीं, अप्रेंटिसशिप के लिए सीआईआई स्किल, छिदवाड़ा द्वारा 15 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया। मेले में सहभागी कंपनियों द्वारा ट्रेनी, सहायक, कॉल सेंटर, फील्ड वर्कर, मशीन ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, तकनीकी सहायक एवं सुरक्षा गार्ड सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संपादित की गई।

सिवनी की राधिका कश्यप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मध्यप्रदेश का गौरव

एकेएफ कुमिते जज-ए परीक्षा उत्तीर्ण कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

सिवनी के कराते जगत में हर्ष की लहर जिले की प्रतिभाशाली कराते खिलाड़ी एवं अधिकारी सेंसेई राधिका कश्यप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए **AKF Kumite Judge-A** की प्रतिष्ठित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर सिवनी सहित पूरे मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एशियन कराते फेडरेशन (यूएन) द्वारा अम्मान, जॉर्डन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराते कार्यक्रम के दौरान 4 सितंबर से 7 सितंबर 2026 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण एवं निर्णायक परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इसी दौरान आयोजित कठिन यहड़हड़हड़ धूहसहड़हड़ परीक्षा में राधिका कश्यप ने सफलता प्राप्त की।

सिवनी की बेटी ने हासिल किया अंतरराष्ट्रीय मुकाम राधिका कश्यप की इस सफलता को कराते जगत में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। कठिन परीक्षा एवं विभिन्न मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए उन्होंने यूएन



यहड़हड़हड़ धूहसहड़हड़ की योग्यता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से सिवनी जिले के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं कराते प्रेमियों में खुशी का माहौल है। राधिका कश्यप की इस उपलब्धि के पीछे उनके निरंतर अभ्यास, अनुशासन, मेहनत और वरिष्ठ कराते अधिकारियों के मार्गदर्शन

की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए राधिका कश्यप को निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग एवं अवसर प्रदान करने में हंशी भरत शर्मा सर (प्रेसिडेंट, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन) एवं शिहान महेश कुशावहा, इंदौर (जनरल सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश भारत कराते एसोसिएशन) का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन ने राधिका को इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी में सपोर्ट करते एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शिहान राजेंद्र सिंह तोमर सर एवं रेफर्री कमीशन के अध्यक्ष प्रतीक शर्मा जी एवं यहूहू के आर सी मेंबर शिहान अनुप देते सर मुंबई एवं टी.एस. शोताकान कराते डू एसोसिएशन इंडिया के प्रेसिडेंट शिहान सुनील देशमुख सर एवं जनरल सेक्रेटरी शिहान सचिन कोकन सर एवं म.प्र. के प्रेसिडेंट शिहान ओमकार कश्यप सर, माउंट लिटर जी स्कूल के डायरेक्टर अकिंत मातू जी, मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर जनक तिहारी जी, एवं सिवनी

विधायक दिनेश राय मुनमुन जी, गुरुकुल पब्लिक स्कूल डायरेक्टर नरेश सिंह राजपूत जी, डॉ. सुनील अगवाल जी, खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सिवनी मनु धुर्वी जी, डॉ. सिद्धू सर, हॉकी संघ के जर्जेंट सेक्रेटरी मकसूद मिर्जा जी, पृथ्वी टाइटन्स के संपादक पृथ्वीराज जगने, नवभारत के ब्यूरो चीफ मौजू रावेक्षिया एवं समस्त कराते प्रशिक्षक एवं खेल संघ एवं नगर वासियों ने म.प्र. के प्रथम एशियन कराते फेडरेशन की जज की परीक्षा पास करने पर कराते जगत से जुड़े पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों एवं शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। राधिका कश्यप की सफलता सिवनी एवं मध्यप्रदेश के उन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो कराते के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का सपना देखते हैं। यह उपलब्धि मेहनत, अनुशासन, समर्पण और गुरुजनों के मार्गदर्शन का परिणामदायक उदाहरण है।



5 बसें, 2 ट्रैक्टर, चार पहिया वाहनों और जमीन-मकान के दस्तावेज जांच के घेरे में; बैंक खातों व बीमा पॉलिसियों की भी पड़ताल, EOW के अनुसार ज्ञात आय की तुलना में करीब 500 गुना अधिक संपत्ति का दावा

मनेरी सेवा सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक विलास चौरे के घर EOW की दबिश

12 साल की नौकरी, 25 लाख ज्ञात आय और संपत्तियों का जखीरा

हरिभूमि न्यूज लांजी।

लांजी क्षेत्र की मनेरी सेवा सहकारी समिति में प्रभारी प्रबंधक के पद पर कार्यरत विलास चौरे के नीमटोला स्थित आवास पर गुरुवार सुबह आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जबलपुर की टीम ने दबिश दी। सुबह करीब 6 बजे पहुंची EOW की टीम में लगभग डेढ़ दर्जन अधिकारी-कर्मचारियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। टीम द्वारा आवास एवं उससे जुड़े ठिकानों पर पहुंचकर दस्तावेजों, बैंक खातों, वाहनों, जमीन-मकान और अन्य संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की गई।EOW की ओर से सामने आई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विलास चौरे की करीब 12 वर्ष की नौकरी से ज्ञात आय लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। जांच के दौरान उनकी आय के मुकाबले कई गुना अधिक संपत्ति और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी मिलने का दावा किया गया है। एजेंसी के अनुसार प्रारंभिक जांच में ज्ञात आय की तुलना में संपत्ति का अंतर करीब 500 गुना तक सामने आया है। हालांकि, संपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन और आय के वैध स्रोतों से अंतिम मिलान की प्रक्रिया जांच का हिस्सा है।

बसें, दो ट्रैक्टर और चारपहिया वाहन जांच के दायरे में

EOW की कार्रवाई के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक जांच टीम को पांच बस, दो ट्रैक्टर, तीन दोपहिया वाहन और चार चारपहिया वाहनों से संबंधित रिकॉर्ड मिले हैं। इसके अलावा मकान तथा बिसोनी में कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है।जांच के दौरान विभिन्न संपत्तियों से



संबंधित कागजात के साथ-साथ बैंक खातों, निवेश और बीमा पॉलिसियों से जुड़े दस्तावेज भी अधिकारियों के सामने आए हैं। परिवार के नाम से कृषि यंत्रों के कारोबार से संबंधित जानकारी की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है।वहीं, 'मातोश्री' नाम से बालाघाट से हैदराबाद मार्ग पर बसों के संचालन से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में होने की जानकारी दी गई है। अब EOW द्वारा इन परिसंपत्तियों के स्वामित्व, खरीद के स्रोत और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन का मिलान किया जा रहा है।

2014 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई थी शुरुआत

प्राप्त जानकारी के अनुसार विलास चौरें की सेवा सहकारी समिति में नियुक्ति वर्ष 2014 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई थी। इसके बाद वे वर्तमान में मनेरी सेवा सहकारी समिति में प्रभारी प्रबंधक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।EOW की जांच केवल निजी संपत्तियों तक सीमित नहीं बताई जा रही है। समिति में उनके कार्यकाल के दौरान हुए



वित्तीय एवं प्रशासनिक लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों को भी जांच टीम द्वारा खंगाला जा रहा है। अधिकारियों द्वारा समिति के रिकॉर्ड,

बैंकिंग लेनदेन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का परीक्षण किए जाने की जानकारी है।

बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों की भी पड़ताल

जांच के दौरान EOW की टीम द्वारा संबंधित बैंक खातों में जमा राशि, निवेश, बीमा पॉलिसियों और अन्य वित्तीय साधनों से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है। संबंधित बैंकों से वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र भेजे जाने की बात भी सामने आई है।जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सामने आई संपत्तियों एवं निवेश के लिए धनराशि का स्रोत क्या रहा है और वह संबंधित व्यक्ति की ज्ञात आय तथा अन्य वैध आय-स्रोतों से किस प्रकार मेल खाता है।

किसानों को फसल को बीमारियों से बचाने की दे रहे सलाह कृषि विभाग के अधिकारी कर रहे खेतों का निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी।

विगत एक सप्ताह से क्षेत्र कोचेवाही, शेरपार, गटापायली, डोरली, मुरझड़, सावंगी, कोसरी टोला, सरण्डी सहित अन्य ग्रामों में प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत किसानों के खेत में लगी बीमारी, कीड़े का निरीक्षण, आकलन करने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण करते हुए किसानों को आवश्यक सलाह एवम मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में किसानों के खेतों में जाकर कृषकों के साथ स्थिति का ध्यानपूर्वक जायजा लिया गया। कृषकों के खेतों में समय से पहले फसलों में आई महामारी से कृषकों को ढांडस बंधाया गया एवम कृषकों को उचित दवाइयों का फसलों में प्रयोग करने के सलाह दी गई। कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी ने सप्ताह भर से लगातार कृषकों के बीच जाकर किसानों को खेतों में लगी फसल में कीड़े, बीमारी, तना छेदक, ब्लाइट ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, माहो, पत्ती मोड़क आदि बीमारी कीड़े के उपचार बताये।



कृषकों को ब्लाइट ब्लास्ट की रोकथाम हेतु ट्रायसाक्लोजोल, स्ट्रेप्टोसाइक्लीन, करबेन्दासिम 50 प्रतिशत इत्यादि दवाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई। दूसरी तरफ कृषकों के खेत में माहो रसचुसक कीड़े भी दिखाई दिए। जिसकी रोकथाम हेतु कृषकों को पायमेटेरजिन 30 प्रतिशत, थाय मेथ्सम 18 प्रतिशत, एलेमदा दवाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई। कृषकों के खेतों में तनाछेदक हेतु क्लोरोसिफर 50S, प्रोफेनोफास इत्यादि दवाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई।

जिला पंचायत बालाघाट के पूर्व सदस्य राहुल सिंह बिसेन द्वारा जानकारी दी गई कि भेरे खेत में लगभग 60-70 एकड़ में केत द्वारा रोपा लगाया गया है, जिसमें किसी

प्रकार का कोई भी कीड़ा व बीमारी नहीं लगी है। श्री बिसेन ने बताया कि हमने जैविक प्राकृतिक खेतों का प्रयोग किया हैं, जिसमें पूरी तरह से तो जैविक नहीं हैं, फिर भी 50-50 प्रतिशत हमने जैविक का प्रयोग किया है।

कृषि महाविद्यालय मुरझड़ फार्म के वैज्ञानिक डॉ उत्तम बिसेन द्वारा कृषि महाविद्यालय से प्रदर्शन के रूप में फिलिपीन्स की 5 किस्मों का प्रयोग किया गया है, जो बहुत अच्छी स्थिति में एक डेमो के रूप में देखने योग्य है। इस सफलतम प्रयोग के लिए कृषि महाविद्यालय मुरझड़ फार्म के वैज्ञानिक एवम प्रोफेसर डॉ. उत्तम बिसेन एवम कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी बघाई के पात्र हैं, जिन्होंने हमें सलाह देकर सफलतम प्रयोग किया है।

वाई 10-11 के रहवासी हुए लामबंद, अवैध ढाबे बंद कराने की मांग अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा

हरिभूमि न्यूज कटंगी। शहर के वाई क्रमांक 10 और 11 मुंडीवाड़ा में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अब रहवासी लामबंद हो गए हैं। मुंडीवाड़ा में देसी-विदेशी शराब के साथ कच्ची शराब की बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। रहवासियों का कहना है कि अवैध शराब की उपलब्धता से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है और शाम होते ही महिलाओं और परिवारों को असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहीं युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर भी अभिभावकों में चिंता है। इसी समस्या को लेकर बुधवार रात 9 बजे वाईवासियों की पानी टंकी चौक में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बड़ी संख्या में महिलाओं और रहवासियों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वाई में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ सामूहिक रूप से अभियान चलाया जाएगा और पुलिस-प्रशासन के सहयोग से इस पर प्रभावी रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा।

महिलाओं की बनेगी विशेष समिति: बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दोनों वाडों की महिलाओं की एक समिति गठित करने का लिया गया। यह समिति मुंडीवाड़ा में अवैध शराब बिक्री की गतिविधियों पर नजर रखेगी। यदि किसी स्थान पर अवैध शराब बिक्री की जानकारी मिलती है तो समिति पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग करेगी। महिलाओं का कहना है कि मुंडीवाड़ा में शराब की अवैध बिक्री के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शाम के समय शराब के नशे में लोगों की आवाजाही बढ़ने से परिवारों में चिंता का माहौल रहता है। ऐसे में महिलाओं ने स्वयं आगे आकर इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया है।



बैठक के बाद थाने पहुंचा दल: बैठक समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में वाईवासी एकजुट होकर पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को मुंडीवाड़ा में अवैध शराब बिक्री की जानकारी दी और प्रभावी कार्रवाई की मांग रखी। वाईवासियों ने पुलिस से कहा कि यदि समय रहते अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका असर यहां के सामाजिक वातावरण और युवा पीढ़ी पर और अधिक पड़ सकता है। पुलिस की ओर से रहवासियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया गया और अवैध शराब बिक्री की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही गई।

अवैध ढाबों पर भी कार्रवाई की मांग: वाईवासियों ने बस स्टैंड से लेकर मुंडीवाड़ा रोड तक संचालित होने वाले ऐसे ढाबों की जांच और कार्रवाई की मांग भी की है, जहां शाम ढलते ही अवैध शराब की बिक्री होती है। रहवासियों का कहना है कि कुछ स्थानों पर शाम के बाद शराब की बिक्री और सेवन के कारण स्थिति बिगड़ जाती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बस स्टैंड से मुंडीवाड़ा रोड तक सभी संबंधित ढाबों और संदिग्ध स्थानों की जांच की जाए तथा यदि नियम विरुद्ध गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

बिरसा-बैहर के 56 गांवों में सघन स्वास्थ्य अभियान

बालाघाट। जिले के बिरसा एवं बैहर क्षेत्र के 56 ग्रामों में मौसमी बीमारियों एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सर्दी-खांसी, बुखार, चर्मरोग, मोजल्स, स्केबीज और मलेरिया सहित विभिन्न बीमारियों से प्रभावित मरीजों की जांच एवं उपचार किया जा रहा है। 17 सितंबर तक अभियान के दौरान कुल 39,018 मरीजों की जांच की गई। इनमें सर्दी-खांसी एवं बुखार के 4,864, मलेरिया के 997, दाने के साथ बुखार के 344 तथा चर्मरोग के 255 मरीज चिन्हित हुए। इस प्रकार कुल 6,460 मरीजों की पहचान की गई।

वन हेल्थ, वन फ्यूचर’ की थीम पर मनेगा 11वां आयुर्वेद दिवस

बालाघाट। आयुर्वेद के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 11वां आयुर्वेद दिवस 15 से 23 सितंबर तक विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय एवं संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार इस वर्ष की मुख्य थीम “Ayurveda for a Healthier Tomorrow” रखी गई है। आयोजन की टेगलाइन “One Health, One Future: Integrating Ayurveda Science through Evidence, Innovation, and Holistic Care” है। जिला

आयुष अधिकारी डॉ. सवेदिता कुमरे ने बताया कि अभियान के तहत जिले के विभिन्न आयुष संस्थानों में स्वास्थ्य एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, पोषण एवं आयुर्वेद जागरूकता, सिकल सेल जांच, योग-ध्यान, प्रकृति परीक्षण, जीवनशैली परामर्श तथा गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच शामिल है। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में आयुर्वेद और स्वस्थ जीवनशैली को लेकर जागरूकता कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी।

॥ ऊँ बृहस्पति नमः ॥

मो.नं. 8827176654
9301826486

वैद्य सुरेश बंशकार

ए एम पी दिल्ली। डी आई एन। आ.स.सै. 5042। 1265

हड्डी रोग तज्ञ

विशेष दिन: शनिवार (पलारी चौराहा जिला सिवनी)

निवास स्थान लामता: लामता रेलवे स्टेशन के पास जिला बालाघाट (म.प्र.)

मंडई सर्किल में भ्रष्टाचार चरम पर, एस.सी.आई. कूपो में रखरखाव के नाम पर भारी झोलझाल

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

वनमंडल उत्तर सामान्य बालाघाट अंतर्गत पूर्व बैहर की सर्किल मंडई में प्रभारी रूपलाल टेकाम के द्वारा एस.सी.आई. कूपो में रखरखाव कार्य के फर्जी भुगतान प्रमाणक तैयार कर भुगतान किया गया है। मिली जानकारी अनुसार सर्किल प्रभारी के द्वारा कूप नं. 7, 9, 10 में रखरखाव कार्य किया जाना था। किन्तु सर्किल प्रभारी तथा बीटगार्ड की सांठ-गाठ से कूपों पर कार्य नहीं किया गया है और राशि में बंदरबाट किया गया है।

कौन है रूपलाल टेकाम

सत्र 2026 में प्रमोशन लिस्ट में नाम आते ही टेकाम के द्वारा मंडई सर्किल को लपकने में जरा भी विलंब नहीं किया गया। मंडई सर्किल प्रभारी से पहले खुदुरगांव बीट में बीट प्रभारी के रूप में कार्यरत रूपलाल टेकाम के द्वारा वर्ष 2025 में खुदुरगांव बीट में उपचार कार्य के नाम पर लाखों के फर्जी भुगतान कर निजस्वार्थ साधा गया। और सूत्र बताते हैं कि मंडई सर्किल में पिछले माह जंगली सुअर शिकार मामले में पांच आरोपी बनाये गये थे, रूपलाल टेकाम के द्वारा दो आरोपियों को छोड़ने के लिए उनसे निजस्वार्थ साधते हुए शानदार मांडोली कर अपने पद का रोप दिखाते हुए कार्य किया गया।

कोरका से बालाघाट के लिए शुरू हुई नई बस सेवा बैगा बहुल दूरस्थ गांवों के ग्रामीणों को मिलेगी आवागमन की बेहतर सुविधा

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री भगत सिंह नेताम ने बिरसा विकासखंड के ग्राम कोरका से बालाघाट के लिए नई बस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनुपमा नेताम, क्षेत्र की पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

नई बस सेवा शुरू होने से बैगा जनजाति बहुल दूरस्थ ग्रामों के ग्रामीणों को बालाघाट जिला मुख्यालय तक आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। लंबे समय से इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को आवागमन

के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बस सेवा प्रारंभ होने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शासकीय कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बालाघाट आने-जाने में सुविधा होगी।

नई बस सेवा ग्राम कोरका से प्रारंभ होकर बोंदारी, कुंडेकसा, अडोरी, घुम्पुर, लंहागाकन्हार, पाथरी, बिठली, चालिसबोड़ी और सोनेवानी होते हुए बालाघाट पहुंचेगी। इसी मार्ग से बस बालाघाट से कोरका वापस जाएगी। इससे मार्ग में आने वाले अनेक बैगा बहुल गांव सीधे बस सेवा से जुड़ जाएंगे।

नई बस सेवा को बैगा बहुल दूरस्थ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में देखा जा रहा है।

नियमित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होने से ग्रामीणों की जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान होगी और क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही इन गांवों में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी।

ग्रामीणों ने बस सेवा प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नियमित बस सुविधा से क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए आने-जाने में होने वाली परेशानी काफी हद तक कम होगी। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुरू हुई यह सुविधा दूरस्थ गांवों को मुख्यालय से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

होटल-रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों की सघन जांच, खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर सघन जांच एवं निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई एवं डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर साफ-सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए।

जांच के दौरान असादी चाट हाउस, मधुर कलश स्वीट्स तथा मां वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान संचालकों को परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने तथा गुणवत्तायुक्त मिठाई एवं नमकीन का ही विक्रय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

होटल स्वागतम की जांच के

दौरान सौंफ, हल्दी, धनिया, ड्राई फ्रूट, पनीर एवं यूज्ड कुकिंग ऑयल के नमूने जांच के लिए लिए गए। यहां स्वच्छता संबंधी कर्मियां पाए जाने पर सुधार नोटिस जारी किया गया।

इसी प्रकार इंडियन कॉफी हाउस से काली मिर्च, मेथी, कॉफी, हॉग एवं सांभर मसाले के नमूने लिए गए। प्रतिष्ठान में अस्वच्छता पाए जाने पर सुधार नोटिस दिया गया। होटल मिड टाउन की जांच के दौरान पनीर एवं छोला के नमूने लिए गए तथा किचन में अस्वच्छता मिलने पर सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया।

होटल मलिकार्जुन से ड्राई फ्रूट, तंदूरी आटा, बेसन एवं सौंफ के नमूने जांच के लिए लिए गए। वहीं कृष्णा डेयरी एवं लिल्लारे डेयरी का निरीक्षण कर संचालकों को साफ-सफाई एवं स्वच्छता के आवश्यक मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

प्रभावित गांवों में पेयजल स्रोतों की स्वच्छता पर जोर

गिडोरी, चिखली, मुक्की, डुडवा और दुल्हापुर में हैंडपंपों के आसपास ब्लीचिंग का छिड़काव, क्लोरीनेशन और सुधार कार्य

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

जिले के प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा लगातार मैदानी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 17 सितंबर को विभागीय अमले ने प्रभावित क्षेत्र के ग्राम गिडोरी, चिखली, मुक्की, डुडवा और दुल्हापुर में

पेयजल स्रोतों की जांच और स्वच्छता संबंधी कार्य किए।विभागीय टीम द्वारा इन गांवों में हैंडपंपों के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया।

साथ ही पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन की कार्रवाई की गई, ताकि पानी की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके और ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो। अभियान के दौरान गांवों में पेयजल व्यवस्था का मौके पर निरीक्षण करते हुए खराब अथवा आवश्यक सुधार वाले हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य भी किया गया। विभाग द्वारा पेयजल स्रोतों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने तथा पानी को दूषित होने से बचाने के संबंध में ग्रामीणों को आवश्यक समझाइश भी दी

गई।प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पेयजल सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम लगातार गांवों में

पहुंचकर क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग छिड़काव और हैंडपंप सुधार जैसे कार्य कर रही है, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

10

10